

संपादकीय

कला की कसक

कला के संरक्षण के लिये नीति-नियंत्रणों से संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद की जाती है। बहुत संभव है कि यह संरक्षण दैनिक जीवन में किसी तरह की विसंगति पैदा करे, लेकिन भावी पौढ़ियों को अतीत के कला सौदर्यों से रुक्खरु करना हर समाज का दायित्व होता है। कला संरक्षण की प्रासंगिकता का प्रश्न पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद फिर सामने उत्पन्न हुआ है, जिसमें सड़क को चौड़ा करने तथा पार्किंग के विस्तार के लिये रॅक गार्डन की दीवार के एक हिस्से को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रकरण विवासत के संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच संतुलन को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। निस्संदेह, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित निर्णय न केवल रॅक गार्डन के निर्माता नेक चंद की कलात्मक विवासत के एक हिस्से को मिटा देता है, बल्कि एक

बहुत संभव है कि यह संरक्षण दैनिक जीवन में किसी तरह की विसंगति पैदा करे, लेकिन भावी पीढ़ियों को अतीत के कला सौंदर्य से रुक्खर करना हर समाज का दायित्व होता है। कला संरक्षण की प्रासांगिकता का प्रश्न पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद फिर सामने उत्पन्न हुआ है, जिसमें सड़क को घूँड़ा करने तथा पार्किंग के विस्तार के लिये रॉक गार्डन की दीवार के एक हिस्से को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रकरण विरासत के संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच संतुलन को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। निस्संदेह, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित निर्णय न केवल रॉक गार्डन के निर्माता नेक चंद की कलात्मक विरासत के एक हिस्से को मिटा देता है, बल्कि एक परेशान करने वाली मिसाल भी स्थापित करता है। जो बताता है कि कि नया भारत विकास के नाम पर अपनी सांस्कृतिक व बन विरासत के साथ कैसा व्यवहार करता है। निस्संदेह, इस तथ्य को लेकर दो राय नहीं हो सकती है कि रॉक गार्डन ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को एक विशिष्ट पहचान दी है। नेकचंद की इस विरासत ने दुनिया को बेकार और अनुपयोगी वीजों को नया रखराय देने की एक नई दृष्टि लाई है।

बनायी गई मूल संरचना का हिस्सा नहीं किलिये दिए जाने वाले तर्क शीलता की किंस्थीकार भी कर लिया जाता है तो भविष्य द्विस्तरों के अस्तित्व पर संकेत मंडरा सकता है। नेत्र प्रतीक के महत्व को उसके ढाँचे के रूप में कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव के रूप में रखा जाता है। इसके बाहरी दृश्यों की सभी विवरणों को तोड़ने के लिये दी जा रही दलीलों की समीक्षा की जाती है। उच्च न्यायालय परिसर के होती है, वह खराब प्रबंधन की देन है। इसमें की कोई भ्रमिका नहीं है। सही मायानों में सेवाओं जैसे टिकाऊ विकल्पों की अनदेखी द्वारा करने वाले अदालत परिसर में देनिक उपरिणिति द्वारा प्रशासन द्वारा दीवार को दूसरी जगह बदला परिस्थितिकीय तरंग के आपरिवर्तनीयता द्वारा ग्रिहण की प्रसिद्ध पेड़ों की विरासत पहले ही में सदियों पुराने पेड़ों को हटाना इसके एक आत्मघाती कदम ही हो सकता है। क माना जाता है।

ਮुगल बादशाही के दौर में कबूतराजों को आपस में लड़ाने वाला 'कबूतरबाजी' एक मशहूर खेल था, मगर कुछ वर्ष पूर्व भारत में कबूतरबाजी लफज मानव तस्करी के रूप में काफी चर्चित हुआ था। कबूतरबाजी यानी लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का तरीका। कबूतरबाजी के इत्तमा ने देश के कुछ मकबूल फनकारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। मौजूदा वक्त में कबूतरबाजी की जगह 'डंकी रूट' एक चर्चित लफज बन चुका है। डंकी रूट यानी किसी देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करना। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन जैसे मुल्क भारतीय युवाओं की पहली प्रसव हैं। जब लोग दस्तावेज नहीं बनवा पाते या विदेश जाने के लिए उनको वीजा नहीं मिलता तो एजेंट्स युवाओं को डंकी रूट के तहत बिना किसी दस्तावेज व वैध वीजा के अवैध तरीके से विदेश पहुंचाने के हसीन ख्वाब दिखाते हैं। जिस प्रकार नशे के सरगना नशा तस्करी के लिए न ए तरीके इजाद करते हैं, उसी प्रकार ट्रैवल एजेंट भी युवाओं को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने के लिए कबूतरबाजी, डंकी रूट व फिशा रूट जैसी अवैध तरकीबें अपनाते हैं। नशे का

परीक्षा के सभी राज्यों में छात्रों की हमारी परीक्षा प्रणाली का दो केवल छात्र, बल्कि अधिभावक और अध्याप मुद्दे की बारीकी में विवेचना की ज़रूरत है। पर्याप्त में एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने की थी, कि इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के प्रोफेसर व्यापारी थे। उनका दर्शन दो प्रकार की घटनाएँ जांच पर आधारित था। उनका मूल विचार यह निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चीजों (घटनाओं सावधानी से जांच करनी चाहिए। इसलिए, वाले पहले दार्शनिकों में से एक हैं। लेकिन प्रणाली का आविष्कार किया या यहां तक कि उनके दिमाग में आया, इससे बहुत अलग है। आकलन करने के लिए परीक्षाएं शुरू कर अभिव्यक्त किया। उन्होंने किसी की जानकारी दिक्कत की जांच करना जरूरी समझा। क्योंकि बारे स्कूल में होता था, तो वह बिना परीक्षा दिया में चला जाता था। लेकिन उनसे एक साल में नहीं लगा सका कि उनसे अपने पाठ्यक्रम हासिल की है। हेनरी फिशेल ने जो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के बारे में जानने के लिए थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उन्होंने 19 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए परीक्षा प्रणाली था, जिससे उन्होंने एक समिति की स्थापना 'राधाकृष्णन समिति' कहा गया और इसका लिया, जिससे भारत में प्रथम परीक्षा प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परतंत्र काल की शिक्षा ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। इस प्रणाली की वजह से आज भी सभी बाबू ही पैदा हो रहे हैं। इसी शिक्षा प्रणाली की वजह से आज भी सभी बाबू ही पैदा हो रहे हैं। हमारे कर्णधारों का ध्यान न क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा आजादी के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की गई। देश में एक विशाल योजना बनाई गई जो शिक्षा का प्रसार कर सके। सैकेंदरी शिक्षा वेसिक शिक्षा समिति बनाई गई जिसका उद्देश्य प्रसार करना था। अखिल भारतीय शिक्षा समिति बच्चों में वेसिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। योजना बनाने के लिए कोठारी आयोग की स्थापना दीर्घी स्तर पर नई योजना लागू करने की

विचारप्रवाह



प्रयागराज महाकुंभ 2001, इस सहस्राब्दी का पहला कुंभ था, जो एक द्वूर्लभ खगोलीय संयोग के चलते 144 साल बाद हुआ है।

महाकृंभ की ऐतिहासिक सफलता पर अनर्गल प्रलाप क्यों?

ललित गर्ग

महाकुभ केवल एक धार्मिक समागम हो नहीं है, यह भारत की संस्कृति का भी परिचयाचक एवं आत्मा है। इस बार महाकुभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, वह अकल्पनीय है, विश्व में इतने विशाल जनसमूह को आकर्षित एवं नियोजित करने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन से विषपक्षी दल एवं नेता बौखलाये हुए हैं और अपने बेतूके एवं अनगत ग्रामपाल से न केवल इस आयोजन की सफलता-गरिमा को धुंधलाना चाहते हैं बल्कि सनातन संस्कृति का उपहास उड़ा रहे हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने महाकुभ को मृत्युकुभ कहा तो सपा सांसद जया बच्चन एवं कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खर्रो कहते हैं कि शवों को गंगा में बहा दिया गया, लाल यादव कहते हैं कि फलतू है महाकुभ। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए हैं। ऐसे एवं कुछ अन्य विषपक्षी नेताओं के भाषक, त्रासद एवं गुरुमठ करने वाले बयानों से वहाँ जाने वाले लोगों को भयभीत, आरंकित और आशंकित किया गया। इन विषपक्षी नेताओं का एक वर्ग, धर्म का मखौल एवं उपहास उड़ाते हुए लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकते भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश करती दिखती है। यह समझ आता है कि कुछ तथाकथित प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्षतावादी लोगों को सनातन धर्म से जुड़ा हर पर्व और परंपरा रास नहीं आती, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे अन्य मतावलींवारों के ऐसे धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों पर उसी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जैसी उन्होंने महाकुभ को लेकर की। आखिर हिन्दू समाज अपने अस्तित्व एवं अस्मिता पर हो रहे हैं इन हमलों एवं आघातों के लिये कब जागरूक एवं संगठित होगा? प्रयागराज महाकुभ 2001, इस सहस्राब्दी का पहला कुंभ था, जो एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के चलते 144 साल बाद हुआ है। जिसमें लगभग 62 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान, रहने, चिकित्सा, यातायात व्यवस्था, भौमि प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा की शानदार एवं ऐतिहासिक व्यवस्थाएं करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने न केवल देश बल्कि दुनिया को चौंकाया है। यह

A wide-angle photograph capturing a massive gathering of people on a riverbank. The foreground is filled with numerous small, colorful boats of various types, packed closely together on the water. In the background, a dense, sprawling crowd of people stretches across the land, extending towards a long, multi-lane bridge that spans the width of the scene. The sky above is a clear, pale blue.

तुनिया का पहला विशाल आयोजन है, जिससे भारत सनातन धर्म का गर्व एवं गौरव तुनिया में बढ़ा है। बावजूद इनिविपक्षी नेता जिस तरह की बातें कह एवं कर रहे हैं, निश्चय ह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, सनातन विमानसिकता को ही दर्शा रहा है, वे लगातार विभाजनवर राजनीति को प्रोत्साहन देते हुए भल जाते हैं कि उनके ऊपर को तोड़ने नहीं, जोड़ने की जिम्मेदारी है। वे जानते नहीं कि क्या कह रहे हैं। उससे क्या नफा-नुकसान हो रहा है य सकता है। वे तो इसलिए बोल रहे हैं कि वे बोल सकते हैं, वोलने की आजादी है, लेकिन इसका नुकसान देश को भगापड़ रहा है। विडम्बना देखिये कि इसका नुकसान उनको उनके दल को भी हो रहा है। भारत में सनातन विरोध राजनीति करके वे अपनी ही जड़े उखाड़ रहे हैं, यह उन राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रहा है। मध्यप्रदेश छतरपुर में बगेश्वर धाम मेडिकल एवं साइंस रिसर्च सेंटर आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाकुंभ उल्लेख करते हुए जिस तरह कुछ विपक्षी नेताओं पर निश्चात्ता और साधा, उसकी आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि कुछ तावस्त्र में अनावश्यक और अर्नगल टीका-टिप्पणी करने वाले हुए हैं। पुरानी कहावत है, मियाँ को न पाँऊं तो बीची को न खाऊं वाली स्थिति विपक्षी नेताओं एवं दलों की हो चुकी है। छिद्राचेषी मानसिकता ही कहा जाएगा। इस प्रकार उद्देश्यहीन, अर्नगल, उच्छ्वस्त्र एवं विवर्धनसात्काम आलोचन किसी का हित सध्यता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। विपक्षी अपने नजरए को बदलें और देश में नफरत और झूठराजनीति करके भ्रम फैलाने की ओष्ठी राजनीतिक हरकतें

बाज आएं। विपक्ष जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, वह किसे भी सम्भव समाज को शोभा नहीं देती। विपक्षी नेताओं ने सारी हांल-अंधेरे हुए जो तुलनाएँ की, जो अनर्गल प्रलाप किया है वह निश्चित रूप से अतिरेक या अतिशयोक्ति कही जा सकती हैं प्रतीत होता है हर दिखते समर्पण की पीठ पर स्वार्थ चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार हर अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं स्वार्थ कहीं राजनीति है, सत्तापक्ष को नुकसान पहुंचाने की ओछी मनवृत्ति है। कुछ विपक्षी नेताओं ने चुन-चुनकर इस आयोजन कर्ता समस्या ओं को गिनाने में अतिरिक्त दिलचस्पी दिखाई और इस क्रम में वहां मची भादड़ का जिक्र करते हुए यहां तक कहा विं उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। यह गैरजिम्मेदारी मानसिक दिवालियापन एवं अपरिक्वत सोच के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को कठघरे में खड़ा किया, क्योंकि वे हिन्दू आस्था पर जानवृक्षक प्रहार ही कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि महाकुंभ भारत की संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। यह टीके ही विं जिस आयोजन में प्रतिदिन एक-दो करोड़ लोगों की भारीदारी होती हो, वहां कुछ समस्याएँ हो सकती हैं और वे दिखीं भी लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस आयोजन को विफल बताया की कोशिश की जाए अथवा यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं के उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अच्छा हो कि विपक्षी नेता यह समझें कि ऐसे आयोजनों पर उनकी बेजा एवं बेतूर्क टिप्पणियां उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान ही पहुंचाती हैं हिन्दू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी शबल में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से थिए ये लोग हिन्दू मठों, मंदिरों, संतों, संस्कृति व सिद्धांतों पर हमला करते हुए राजनीति करते रहे हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हिन्दू भारत का बहुसंख्य वर्ग है, भारत एक हिन्दू राष्ट्र है, उसका विरोध करते हुए वे अपनी राजनीति जमीन को ही खोखला करते हैं। मोदी-योगी एवं भाजपा विरोध करते हुए वे राष्ट्र एवं सनातन विरोध पर उत्तर आते हैं। हिन्दू पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं, जो धर्म एवं संस्कृति स्वभाव से हैं प्रगतिशील है, विश्व मानवता को जोड़ने वाली है, उस पर्व कीचड़ उछाल कर वे सचिद्र नाव में सवार हैं। हिन्दू समाज कंबांटा, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है।

ੴ

का०

खारजा ने अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए लोगों के ओंकड़े सदन के समक्ष रखे तो जात हुआ कि वर्ष 2009 में 734 साल 2010 में 794, सन-2011 में 597 तथा सन-2012 में 530 भारतीयों को अमेरिका ने अवैध प्रवासी बताकर अपने मुल्क से बाहर किया था। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों वे निवासन का सिलसिला बदस्तर जारी है। भले ही अमेरिका अपने तत्त्व तेवा दिखाकर अवैध प्रवासियों को अपने मुल्क से डिपोर्ट कर रहा है, मारग लोगों से लाखों रुपए हड्डी करके डंकी रूट के तहत विदेश भेजने वाले गिराही व डैरेवल एजेंटों का धंधा भी बदस्तर जारी है। विदेश भेजने वे नाम पर कई राज्यों में सैकड़ों एजेंट अपने दफतर खोल कर बैठे हैं, जो युवाओं को लुभाकर उनसे लाखों रुपए हड्डी करके विदेशों में सुरक्षित पहुचाने का दावा करते हैं। जबविद्या अमेरिका से भारतीय युवाओं के निवासन ने सभी दावों का पोल खोल दी है। यूएसए सहित कई देशों में भारतीय नागरिक नस्तीय भेदभाव का शिकार होते हैं। विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की हत्याएं की जाती हैं। डंकी रूट के तहत विदेशों में गए सैकड़ों भारतीय युवा कई देशों में सलाखों वे पीछे हैं। डंकी रूट डैथ रूट भी सावित हो रहा है।

आप

ନାରାୟା

साइबर मकड़िजाल

यह खबर परेशान करने वाली है कि म्यांमार और पूर्वी एशिया के कई देशों से जो संगठित साइबर अपराध संचालित हो रहे हैं, उनके चंगुल में बड़ी संख्या में भारतीय युवा भी हैं। हाल ही में म्यांमार के दुर्गम इलाकों में बनाये गए साइबर अपराधियों के अड्डों से सत्र भारतीय युवाओं को छुड़ाया गया है। जिनको डरा-धमकाकर भारत में साइबर अपराधियों को अंजाम देने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है साल 2022 के बाद म्यांमार, थाईलैण्ड, लाओस, कंबोडिया आदि से छह सौ से अधिक भारतीयों को अपराधियों के चंगुल में से बचाया जा चुका है। आशंका है कि कई हजार भारतीय युवा म्यांमार समेत विभिन्न देशों में साइबर अपराधियों के अड्डों में जबरन रोके गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय युवा प्रतिभाएं दलालों की सायिंज से संगठित साइबर अपराध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के चंगुल में फंस जाती हैं। विडंबना ही है कि हम अपने युवाओं को न तो रोजगार दे पार हे हैं और न ही विदेशों में अपना भविष्य संवारने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं को फर्जी एजेंटों के चंगुल से बचा पा रहे हैं। आखिर हमारी एजेंसियां ऐसी धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि युवा अपनी जीमान बेचकर व कर्ज उठाकर विदेश जाते हैं, लेकिन एजेंटों की धोखाधड़ी से वे साइबर अपराधियों के शिकंजे में फंस जाते हैं। दरअसल, साइबर अपराधियों का मकड़ाजाल इतना मजबूत हो चुका है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उन पर नियंत्रण कर पाना संभव न होगा। ऐसे वक्त में जब साइबर अपराधियों का नेटवर्क दुनिया की आर्थिकी को चूना लगा रहा है, मिल-जुलकर इनके खिलाफ अभियान चलाना वक्त की जरूरत है। निश्चित रूप से यह एक विकट संकट है, जिसे दुनिया के देशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह जानते हुए कि साइबर अपराधियों का संगठन लगातार ताकतवर होता जा रहा है और वे समानांतर काली अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। दरअसल, हो यह रहा है कि देश-दुनिया में ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वे सुनहरे सपने दिखाकर बेरोजगार युवाओं को फँसाते हैं। उन्हें जगह कोई और बतायी जाती है और अंततः साइबर अपराधियों के अड्डों पर पहुंचा दिया जाता है। युवाओं के पास पोर्ट छीन लिए जाते हैं। ये अड्डे ऐसी जगहों पर होते हैं कि उस देश की पुलिस की पकड़ में वे आसानी से नहीं आते। हाल के वर्षों में साइबर अपराधी इतने चतुर-चालाक हो गए हैं कि निगरानी करने वाली एजेंसियों की पकड़ से आसानी से बच जाते हैं। हाल ही में जिन सत्र भारतीयों को म्यांमार में साइबर अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया गया, उसमें म्यांमार के सीमा सुरक्षा बल की बड़ी भूमिका रही है। इन मुक्त कराए गए भारतीयों में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी व राजस्थान आदि राज्यों के लोग थे। इसी तरह म्यांमार व अन्य पूर्वी एशिया के देशों में साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे हुए भारतीयों को मुक्त कराने के लिए इन देशों की सरकारों से सह योग मांगा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर साइबर अपराधियों द्वारा संचालित अपराधों की लगातार मजबूत होती काली अर्थव्यवस्था परी दुनिया की आर्थिक व कानूनी सुरक्षा के लिये चुनौती है। दरअसल, इस काले धन से नश के कारोबार, आतंकवाद और मानवीय तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इस संगठित आपराधिक नेटवर्क पर अविलंब अंकुश लगाने की जरूरत है।

परीक्षा प्रणाली में कैसे करें सुधार

देश के सभी राज्यों में छात्रों की परीक्षा का दौर शुरू है। यह हमारी परीक्षा प्रणाली का दोष है कि परीक्षाओं को लेकर न केवल छात्र, बल्कि अभिभावक और अध्यापक भी तनाव में आ जाते हैं। इस मुद्दे की बारीकी में विवेचना की जरूरत है। परीक्षाओं की शुरुआत 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी दाशनिक ने की थी, जिनका नाम सर हेनरी फिशेल था। वह अमेरिका के एक व्यापारी थे। उनका दर्शन दो प्रकार की घटनाओं (बाहरी और अंतरिक) की जांच पर आधारित था। उनका मूल विचार यह है कि किसी व्यक्ति को किसी नेतृत्व पर पहुंचने से पहले चीजों (घटनाओं, व्यक्तियों आदि) की बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए। इसलिए, वह जांच के दर्शन को अपनाने वाले पहले दाशनिकों में से एक हैं। लेकिन यह कहना कि उन्होंने परीक्षा प्रणाली का आविष्कार किया या यहां तक कि चीजों की जांच करने का विचार उनके दिमाग में आया, इससे बहुत अलग है। उन्होंने छात्रों के दिमाग का आकलन करने के लिए परीक्षाएं शुरू करने के अपने विचार को भी अभिव्यक्त किया। उन्होंने किसी की जानकारी, शिक्षा, प्रतिबंध, उत्कृष्टता आदि की जांच करना जरूरी समझा। क्योंकि जब कोई बच्चा कॉलेज में पहली बार स्कूल में होता था, तो वह बिना परीक्षा दिए ही एक क्लास से दूसरी क्लास में चला जाता था। लेकिन उसने एक साल में कितना अध्ययन किया, यह पता नहीं लगा सका कि उसने अपने पाठ्यक्रम के बारे में कितनी जानकारी हासिल की है। हेनरी फिशेल ने जो सबसे पहली परीक्षा शुरू की, वह छात्रों के सामान्य ज्ञान के बारे में जानने के लिए थी। हमारे देश में परीक्षा की खोज सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उन्होंने 1948 में एक रिपोर्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिससे उन्होंने एक समिति की स्थापना की। इसके बाद, इसे राधाकृष्णन समिति' कहा गया और इसका सुझाव भारत सरकार ने मान लिया, जिससे भारत में प्रथम परीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परतंत्र काल की शिक्षा प्रणाली माना जाता है। यह ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। इस प्रणाली को लॉर्ड मैकले ने जन्म देया था। इस प्रणाली की वजह से आज भी सफेद कॉलरों वाले लिपिक और बाबू ही पैदा हो रहे हैं। इसी शिक्षा प्रणाली की वजह से विद्यार्थियों का शारीरिक और आत्मिक विकास नहीं हो पाता है। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजात हुआ था। हमारे कर्णधारों की ध्यान नई शिक्षा प्रणाली की तरफ गया और क्षेत्रीकी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुकूल नहीं थी। आजादी के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक समितियां बनाई गईं। देश में एक विशाल योजना बनाई गई जो तीन साल के भीतर 50 फीसदी शिक्षा का प्रसार कर सके। सैकेंडरी शिक्षा का निर्माण किया गया। बाद में बेसिक शिक्षा समिति बनाई गई जिसका उद्देश्य भारत में बेसिक शिक्षा का प्रसार करना था। अखिल भारतीय शिक्षा समिति की सिफारिश की वजह से बच्चों में बेसिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए कोठारी आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर नई योजना लागू करने की सिफारिश की। इस योजना की चर्चा-परिचार लंबे समय तक चली थी। देश के बहुत से राज्यों में इस प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली से दस साल तक दसवीं कक्षा में सामान्य शिक्षा होती है। इसमें सभी विद्यार्थी एक जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। इस पाठ्यक्रम में दो भाषाएं, गणित, विज्ञान और सामाजिक पांच विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा से भी परिचित होना चाहिए। सातवीं की परीक्षा के बाद विद्यार्थी अलग-अलग विषयों पर अध्ययन करते हैं। अगर वो चाहे तो विज्ञान ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, और औद्योगिक कार्यों के लिए क्राफ्ट भी ले सकते हैं। लेकिन इस काव्याद के बांधित परिणाम नहीं निकले। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली को रोजगार को सामने रखकर बनाया गया है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भाग तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती है। ऐसे लोग समाज में अनुशासनहीनता और अराजकता पैदा करते हैं। नई शिक्षा नीति से हमें यह लाभ होगा कि ऐसे विद्यार्थी दसवीं तक ही रह जाएंगे और वे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। जो विद्यार्थी योग्य होंगे, वे कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। दसवीं करने के बाद विद्यार्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें नवीन शिक्षा प्रणाली को सफल बनाना है तो स्थान-स्थान पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम खोलने पड़ेंगे जिससे दसवीं करने के बाद विद्यार्थी कॉलेजों की तरफ नहीं भागें। इससे शिक्षित लोगों की बेरोजगारी में कमी आएंगी और शिक्षित लोगों का समाज में मान-सम्मान होगा। इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और यह भविष्य के निर्माण के लिए भी सहायक होगी। इस प्रणाली को पूरी तरह से सफल बनाने का भार हमारे शिक्षकों पर है। हाल ही में हमाचल प्रदेश में कम संख्या वाले शिक्षा संस्थानों को सीमित करने का फैसला बेहतर साबित होगा क्योंकि इससे फोकस बेहतर होगा। इसी कड़ी में भारत में पेपर लीक की समस्या महंगी और दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली का ही परिणाम है और इससे लोग महंगी पढ़ाई पर खर्च करने के बजाय प्रश्नपत्र खरीदने में लाभ देखते हैं। सरकारी कॉलेज बहुत कम शुल्क लेते हैं जिससे शिक्षा सुलभ हो जाती है। लेकिन वहीं निजी संस्थानों की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए छात्र चाहते हैं कि उन्हें लाखों रुपए की फीस देने के बजाय लीक हुआ पेपर ही मिल जाए। आखिर में यह कहना चाहूँगा कि हमें तय करना होगा कि छात्र सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए भी तैयार हों। मशिवरा है कि हर छात्र को मजबूत भविष्य बनाने के लिए कोई स्किल सीखना चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी कोर्स से जुड़ा हो। याद रहे कि व्यावहारिक शिक्षा, व्यवस्थित सुधार एवं कौशल विकास के द्वारा ही युवाओं को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के विषय में कहा था कि शिक्षा का अर्थ बच्चों में सारी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास करना होता है। शिक्षा, एक डमी के दायरे से बढ़कर होनी चाहिए, छात्रों को रोजगार क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। हमें हर साल नए कौशल सीखने चाहिए, फिर चाहे वह डाइविंग हो या कोई और चीज। सही कौशल पाने से आपकी रोजगार क्षमता बढ़ती है।

महाकुंभ के लिए रेलवे ने चलाई 16 हजार ट्रेन

एजेंसी

नई दिल्ली : महाकुंभ के समापन के कुछ घंटे बाद रेल मंत्री अधिकारी वैष्णव प्रयागराज जंक्शन संपर्क कई रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेल मंत्री ने रेलवे की अलग-अलग यूनिट्स की ओर से किंवद्ध कामों का जायजा लिया और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। उहाँने महाकुंभ के दौरान बेहतर काम करने वाले रेलकर्मियों की साराहना की, उनकी पीठ थपथपाई और कुछ को सम्प्रीत भी किया। रेल मंत्री ने कर्मचारियों से हाथ मिलाकर उनके योगदान को साराहा और कुछ कर्मचारियों को गले लगाकर उनकी



किंवद्धिया की बजह से महाकुंभ का सदेश दुनिया तक पहुंचा। साथ ही ये भी कहा कि 6 साल बाद होने वाले कुंभ मेले के लिए रेलवे अभी से योजनाएँ बनाएगा और बड़े स्तर पर तैयारी करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि महाकुंभ के दौरान साड़े चार करोड़ ये ज्यादा श्रद्धालुओं ने ट्रेनों में सफर किया। उहाँने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं।

प्रयागराज दौरे के दौरान रेल मंत्री ने जांस्चरियों से भी मुख्यमंत्री और सुनिधित की जा सकी। उनके दौरे में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार और बाकी सीमित अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरे से रेलवे कर्मचारियों का किसी बाधा के सपन हुआ। उहाँने मीडिया का आधार जाते हुए कहा-

केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात कर डॉ. कौशल ने उन्हें पौधा भेंट किया

एजेंसी

नई दिल्ली : नई दिल्ली 17 अकबर रोड स्थित केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर दौरे में अफ़ झारखांड व विश्व व्यापी पर्यावरण संरक्षण अधियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व वनरक्षी मूलमेंट के प्रणेता डॉ. कौशल किशोर जायसवाल और वौयोप्साए संस्था के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुपार तिवारी ने पर्यावरण धर्म के तहत तमिलनाडु के रक्षणात्मक पौधे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनीत के संहित को भेट कर उनका स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान डॉ. कौशल ने कहा कि प्रवक्ता के सुखद संयोग से आज समाज के दो महान रक्षकों को एक साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस दोनों रक्षक में इतना फर्क है कि माननीय मंत्री जी के निर्वाचन में देश की सरहद की रखवाली हो रहा है।



उहाँने यह भी बताया कि उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण और जल संग्रह का नियमन कराया गया है। जहाँ 22 देशों की कई विलुप्त कार्यक्रम के तीन दिवसीय दौरे में प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। डॉ. कौशल ने रक्षा मंत्री को यह भी बताया कि चंदन एक ही ग्रीन के ग्राम पर्यावरण डाली जाना के लिए दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म जान मंत्री का नियमन कराया गया है। जहाँ रक्षण एवं चंदन के पौधे लगाए गए हैं। डॉ. कौशल ने रक्षा मंत्री को यह भी बताया कि चंदन एक ही ग्रीन के ग्राम पर्यावरण डाली जाना के लिए दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म जान मंत्री का नियमन कराया गया है। जहाँ रक्षण एवं चंदन के पौधे लगाए गए हैं।

सरकारी
प्रतिभूतियों में
निवेश करना हुआ
अब और भी
आसान...

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप

का उपयोग करके
कभी भी, कहीं भी
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें,
जिनमें शामिल हैं

- खजाना बिल
- सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड
- अस्थिर दर बचत बॉण्ड 2020

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए स्कैन करें

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के फायदे:

- सरकारी प्रतिभूति बाजार तक आसान पहुंच
- तुरंत लॉगइन, सरल यूजर इंटरफ़ेस और आसान नेविगेशन
- भुगतान के कई विकल्प - नेट बैंकिंग, UPI और NACH
- परिपक्वता पर गारंटीकृत लाभ, शून्य ब्रोकरेज और अन्य कोई शुल्क नहीं

अधिक जानकारी के लिए, <https://rbiretaildirect.org.in> पर विजिट करें
हमें यहाँ लिंक: support@rbiretaildirect.org.in



सरकारी
प्रतिभूतियों में
निवेश करना हुआ
अब और भी
आसान...

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप

का उपयोग करके
कभी भी, कहीं भी
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें,
जिनमें शामिल हैं

- खजाना बिल
- सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड
- अस्थिर दर बचत बॉण्ड 2020

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए स्कैन करें



जानहित में जारी
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

28,945

टैब का वितरण

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालय एपोर्ट कार्ड एवं शिक्षकों के लिए
50 घंटे का अनिवार्य 'समेकित - सतत क्षमता विकास'

कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ

दिनांक
28 फरवरी, 2025

समय
12:00 बजे मध्याह्न

स्थान
प्रोजेक्ट भवन सभागार,
धूरा, रांची

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्री दामदास सोरेन

माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग

